सुषमा ने संभाली लखनऊ के महापौर... 8 | आजम खान पर फैसला, शुरू... 3 | मोदी सरकार के नाकामी-बदहाली... 7

सांध्य दैनिक
4PM
जिद...सच की
www.4pm.co.in | www.facebook.com/4pmnewsnetwork | @Editor_Sanjay | YouTube @4pm NEWS NETWORK
• वर्ष: 9 • अंक: 109 • पृष्ठ: 8 • लखनऊ, शुक्रवार, 26 मई, 2023
मूल्य ₹ 3/-

बड़ी सावधानी और चतुराई से अपने कदम बढाइये और याद रखिये की जीवन संतुलन बनाये रखने का एक महान काम है।

-डॉ. सिअस

नए संसद भवन के उद्घाटन की याचिका को सुप्रीम इंकार

शीर्ष अदालत ने कहा-ऐसी याचिकाओं को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, लगाई फटकार, दोबारा आए तो लगेगा जुर्माना

- याचिकाकर्ता ने पिटीशन वापस ली
- 25 दल पक्ष में 20 ने किया विरोध

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। संसद भवन की नई इमारत के उद्घाटन को लेकर जारी विवाद से संबंधित जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से ही इंकार कर दिया। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम जानते हैं कि यह याचिका क्यों दाखिल हुई। ऐसी याचिकाओं को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट ने पूछा कि इस याचिका से किसका हित होगा? इस पर याचिकाकर्ता सटीक जवाब नहीं दे पाए। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा अगर ऐसी याचिका दोबारा लगाई गई तो कोर्ट जुर्माना भी लगा देगा।

सुप्रीम कोर्ट के वकील सीआर जया सुकिन ने यह जनहित याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा गयाकि उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को शामिल नहीं करके भारत सरकार ने भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है। ऐसा करके संविधान का सम्मान नहीं किया जा रहा है। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने पिटिशन वापस ले ली। उन्होंने कहा कि वे हाईकोर्ट भी नहीं जाएंगे। सुकिन ने गुरुवार को यह याचिका दायर की थी।

नए संसद भवन पर केंद्र सरकार के साथ अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) मिलाकर 25 दल हैं। वहीं, उद्घाटन कार्यक्रम के बहिष्कार की विपक्ष की मुहिम से कई दलों ने किनारा कर लिया है। बसपा, जद-एस और तेलुगू देशम ने समारोह में शामिल होने का एलान किया। एनडीए में भाजपा समेत 18 दलों के अलावा अन्य सात दलों ने उद्घाटन समारोह में शिरकत करने की रजामंदी दी है। कांग्रेस समेत कुल 21 विपक्षी दलों ने बहिष्कार की घोषणा की है।

75 का सिक्का करेगी जारी सरकार

प्रधानमंत्री 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे. इस दौरान 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि नए संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में 75 रुपये का एक विशेष सिक्का लॉन्च किया जाएगा। सिक्के के एक तरफ अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा। बाईं ओर देवनागरी लिपि में भारत और दाईं ओर अंग्रेजी में इंडिया शब्द लिखा होगा।

फैसले पर पुनर्विचार करे विपक्ष , ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनें : राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि कोई भी इसका राजनीतिकरण न करें, नई संसद लोकतंत्र का प्रतीक है और सभी भारतीयों की आकांक्षा है। नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करने का फैसला करने वाली सभी पार्टियों से मेरी अपील है कि वे अपने फैसले पर फिर से विचार करें। 28 मई को प्रधानमंत्री नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित कर भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। नया संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक संकल्प के साथ 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान और उनकी आकांक्षाओं की भी अभिव्यक्ति है। संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है जो 21वीं सदी में फिर नहीं आएगा। इस शुभ अवसर पर संसद या राष्ट्रपति को विवाद में लाने से किसी को भी बचना चाहिए। हमें सवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह में अंतर समझना चाहिए। तकनीकी दृष्टि से यह संसद का कोई सत्र नहीं बुलाया गया है, यह भवन के उदघाटन का समारोह है मैं आग्रह करूंगा कि जिन राजनीतिक दल अपने फैसले पर फिर विचार करें।

सेंगोल, 24 में सत्ता परिवर्तन का प्रतीक : अखिलेश

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नए संसद के उद्घाटन में सेंगोल की मौजूदगी को लेकर प्रतिक्रि या दी है। अखिलेश ने सेंगोल का साल 2024 के लोकसभा चुनाव से खास कनेक्शन बताया है, अखिलेश यादव ने दावा किया कि अगले साल लोकसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। पूर्व सीएम ने ट्वीट किया- सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण (एक-हाथ से दूसरे हाथ में जाने) का प्रतीक है, लगता है भाजपा ने मान लिया है कि अब सत्ता सौंपने का समय आ गया है।

राहुल को दिल्ली के कोर्ट से बड़ी राहत

- साधारण पासपोर्ट से जा सकते हैं विदेश
- तीन साल के लिए जारी की एनओसी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने शुक्रवार को नए पासपोर्ट को लेकर दायर याचिका को मंजूर कर लिया है। यानी उन्हें नया पासपोर्ट बनाने के लिए मंजूरी मिल गई है।

राहुल गांधी ने कोर्ट से पासपोर्ट बनवाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने की मांग की थी। कोर्ट ने तीन साल के लिए एनओसी जारी की है। इस तरह उनका पासपोर्ट तीन साल तक के लिए वैध होगा।

सुब्रमण्यम स्वामी ने किया अर्जी का विरोध

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की दलीलों के बाद सुनवाई को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की अर्जी का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि अगर राहुल विदेश जाते हैं तो नेशनल हेराल्ड मामले की जांच प्रभावित हो सकती है।

इसलिए बनवा रहे नया पासपोर्ट?

बता दें कि संसद की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। राहुल ने अब साधारण पासपोर्ट बनवाने के लिए अप्लाई किया है। राहुल नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं, लिहाजा उन्हें नया पासपोर्ट बनवाने के लिए एनओसी की जरूरत है।

सत्येंद्र जैन को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत

- सुप्रीम कोर्ट से बीमारी के चलते मिली राहत

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बीते एक साल जेल में बंद सत्येंद्र जैन को 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत दे दी है। उनको यह जमानत स्वास्थ्य आधार पर गिरती हुई सेहत में सुधार के लिए दिया गया है। बीते कुछ दिनों से जैन की तबियत खराब थी। गुरुवार को वह जेल के वाशरूम में गिर पड़े थे जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया।

सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत को लेकर की जाने वाली सुनवाई का ईडी ने विरोध किया। ईडी की तरफ से पेश वकील ने कहा सत्येंद्र जैन दिल्ली में जेल और स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं लिहाजा एलएनजेपी अस्पताल की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, हमारी मांग है कि एम्स के डॉक्टरों का एक स्वत्रंत मेडिकल बोर्ड उनके स्वास्थ्य की जांच करे और उसके आधार पर अगर ऐसा लगता है कि उनको जमानत दी जानी चाहिए तो अदालत अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है।

अदालत ने कहा

अदालत में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। मैं आज सिर्फ स्वास्थ्य आधार पर जमानत दिए जाने की मांग कर रहा हूं, इस पर ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसीटर जनरल पी एस राजू ने कहा, एम्स के पैनल की तरफ से स्वास्थ्य जांच हो, यह दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, डॉक्टरों को जानते हैं, इनकी जांच एम्स या आएएमएल के पैनल से जांच की जाए।

संसद भवन का उद्घाटन हो रहा या बीजेपी कार्यालय का : सामना

» आडवाणी को उद्घाटन में आमंत्रित किया गया या उन्हें भी गेट पर ही रोका जाएगा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई। नए संसद भवन के उद्घाटन पर मचे रार के बीच उद्धगुट शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी पर ताजा जुबानी हमला बोला है। मुखपत्र सामना में भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल लाल कृष्ण आडवाणी का जिक्र करते हुए कटाक्ष किया गया है। संपादकीय में यह भी आरोप लगाया गया है कि पीएम मोदी, संसद का उद्घाटन इस तरह कर रहे हैं, मानों वह भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर हो, इतना ही नहीं शिवसेना ने सरकार के उस कदम की आलोचना भी की है जिसमें नेता विपक्ष को उद्घाटन में निमंत्रण नहीं दिया गया है।

सामना की संपादकीय में लिखा गया है– नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली में भाजपा मुख्यालय के भव्य उद्घाटन की तरह ही किया जाएगा। संसद में विपक्ष के नेता का पद प्रधानमंत्री के बराबर होता है। निमंत्रण पत्र पर नेता प्रतिपक्ष का नाम होता तो लोकतंत्र की शोभा बढ़ जाती। संसद की अध्यक्ष महामहिम द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित नहीं किया गया। पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का जिक्र कर सामना में पूछा गया है– बीजेपी को अच्छे दिन दिखाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी को उद्घाटन में आमंत्रित किया गया या उन्हें भी गेट पर ही रोका जाएगा! जहां देश के राष्ट्रपति को उद्घाटन समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया, वहां आपको–हमें आमंत्रित किया जाए या नहीं, क्या फर्क है?

सरकार ने बनाया है संसद तो उद्घाटन का उसको ही हक : मायावती

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) सुप्रीमो मायावती ने एक चौंकाने वाले फैसला लिया है। बीएसपी ने 28 मई को संसद के नये भवन के उद्घाटन का समर्थन किया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर लिखा-केन्द्र में पहले चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या अब वर्तमान में बीजेपी की, बीएसपी ने देश व जनहित निहित मुद्दों पर हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका समर्थन किया है तथा 28 मई को संसद के नये भवन के उद्घाटन को भी पार्टी इसी संदर्भ में देखते हुए इसका स्वागत करती है। इसके साथ ही मायावती ने ट्वीट कर लिखा- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा नए संसद का उद्घाटन नहीं कराए जाने को लेकर बहिष्कार अनुचित, सरकार ने इसको बनाया है इसलिए उसके उद्घाटन का उसे हक है। इसको आदिवासी महिला सम्मान से जोड़ना भी अनुचित, यह उन्हें निर्विरोध न चुनकर उनके विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करते वक्त सोचना चाहिए था।

भाजपा सरकार ने पुलिस के सहारे लोकतंत्र को लूटा : बृजलाल खाबरी

» सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खाबरी (पूर्व सांसद) ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। नगर निकाय चुनाव में जनता ने हमें समर्थन दिया लेकिन भाजपा सरकार ने पुलिस के सहारे लोकतंत्र को लूटा है। लोकसभा चुनाव में गठबंधन और सीटों की संख्या पर फैलाए जा रहे भ्रम का खंडन किया।

उन्होंने कहा है कि हमारा गठबंधन जनता के साथ है। हम अनुभवी नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी व प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव 2024 में जनता के बीच जाएंगे। पार्टी प्रवक्ता अंशू अवस्थी ने कहा की कुछ खबरों को बिना किसी आधार के प्रचारित किया जा रहा है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जनता का काफी स्नेह और समर्थन मिला है, जिसका व्यापक असर हुआ है। हमें हिमांचल प्रदेश व कर्नाटक के परिणाम में इसका असर भी दिखा है। आने वाले चुनावों में भी इसका व्यापक असर दिखेगा।

राज्यसभा में अध्यादेश गिरा तो बीजेपी के लिए 24 का चुनाव मुश्किल : केजरीवाल

» दिल्ली सीएम ने शरद पवार से की मुलाकात

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीयय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को मुंबई में एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की। उनके स्वागत के लिए एनसीपी के बड़े नेता वाईबी चव्हाण के बाहर खड़े थे। अजित पवार, छगन भुजबल, सुनील तटकरें स्वागत के लिए मौजूद रहे। इस मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 8 साल तक दिल्ली के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। हमसे लगातार शक्तियां छीनने की कोशिश की गई। संसद में बिल पास होने नहीं देना है, गैर बीजेपी दल साथ आएं तो अध्यादेश गिर जाएगा, ये अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लाया गया है। राज्यसभा में अगर बिल गिर जाता है, तो इसे 2024 का सेमीफाइनल मानिए, बीजेपी सरकार नहीं आने वाली है।

एनसीपी ने हमें दिया समर्थन

केजरीवाल ने कहा कि एनसीपी ने हमें समर्थन दिया है कि राज्यसभा में इसे पास न होने देने के लिए हमारा सहयोग करेंगे। शरद पवार साहब आज के दिन देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। मेरी पवार साहब से विनती है कि खुद तो समर्थन कर रहे हैं देश की दूसरी पार्टियों से भी समर्थन जुटाने में हमारा सहयोग करें। इससे पहले केजरीवाल ने बुधवार को मुंबई में शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की थी।

शांति व खुशहाली के लिए मंदिरों में फहराएंगे पताका : शकुंतला रावत

» राजस्थान चुनाव से पहले गहलोत सरकार का एलान

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

जयपुर। कर्नाटक में मिली जीत के बाद अब कांग्रेस अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार धार्मिक रंग में रंगती नजर आ रही है।

दरअसल, प्रदेश सरकार के देवस्थान विभाग ने गुरु-पुष्य के शुभ संयोग के मौके पर प्रदेश के सभी सरकारी मंदिरों में पीली पताका फहराने का फैसला लिया है। जयपुर के बड़ी चौपड़ स्थित कल्कि मंदिर से इसकी शुरुआत की गई। देवस्थान विभाग की मंत्री शकुंतला रावत ने कहा, कि ध्वजारोहण का एक अलग ही महत्व है। किसी मंदिर के ऊपर झंडा इसलिए ही लगाते हैं कि शांति और खुशहाली की पताका फहरती रहे, इसी तरह पूरे प्रदेश में खुशहाली रहे, ओम शक्ति और सूर्य प्रकाश का प्रतीक है, सूर्य ऐसे देवता हैं जिनके हम साक्षात दर्शन कर सकते हैं।

हिंदुत्व की छवि को मजबूत करने की कोशिश

ये पहली बार नहीं है जब गहलोत सरकार ने अपनी सर्वधर्म समभाव की छवि को मजबूत करने की कोशिश की हो, इससे पहले भी सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के कई प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के विकास के लिए बजट में कई बड़े ऐलान किए थे, इनमें जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का उज्जैन के महाकाल मंदिर की तर्ज पर विकास, चित्तौड़गढ़ में जलझूलनी एकादशी पर सांवरिया सेठ के मेले में बस किराए में 50 फीसदी की छूट, बेणेश्वरधाम और मानगढ़ धाम का विकास जैसे फैसले अहम हैं।

अमूल को निर्देश दे केंद्र सरकार: स्टालिन

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से आग्रह किया कि गुजरात आधारित डेयरी कंपनी 'अमूल को तत्काल प्रभाव से तमिलनाडु में दूध की खरीद बंद करने का निर्देश दिया जाए। स्टालिन ने शाह को लिखे पत्र में तमिलनाडु 'मिल्क शेड क्षेत्र में कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (अमूल) द्वारा दूध की खरीद किए जाने से उत्पन्न मुद्दों पर केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है।

उन्होंने कहा कि हाल में, राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि अमूल ने कृष्णागिरि जिले में 'चिलिंग सेंटर और प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए अपने बहु-राज्य सहकारी लाइसेंस का उपयोग किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके साथ ही, अमूल ने तमिलनाडु में कृष्णागिरि, धर्मपुरी, वेल्लोर, रानीपेट, तिरुपथुर, कांचीपुरम और तिरुवल्लूर जिलों में और आसपास स्थित एफपीओ व एसएचजी के माध्यम से दूध खरीदने की योजना बनाई है।

सीमाओं पर दोहरे खतरे का सामना कर रहा भारत : राजनाथ

बोले- तकनीक के क्षेत्र में अग्रिम होना बहुत आवश्यक

» रक्षामंत्री बोले-आज हम दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक हैं

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपनी सीमाओं पर दोहरे खतरे का सामना कर रहे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए, हमारा तकनीक के दृष्टिकोण में उन्नत होना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आज हम दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक हैं, हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम की चर्चा पूरी दुनिया में होती है।

ऐसे में यह अनिवार्य हो जाता है, कि देश के हितों की सुरक्षा करने के लिए हमारे पास एक तकनीक में आगे सेना हो। आप लोग देख रहे हैं, कि हमारे देश में स्टार्ट-अप्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, और इस प्रकार की साझेदारी हमारे देश में स्टार्ट-अप्स कल्चर को और बढ़ाने में मददगार साबित होगी।

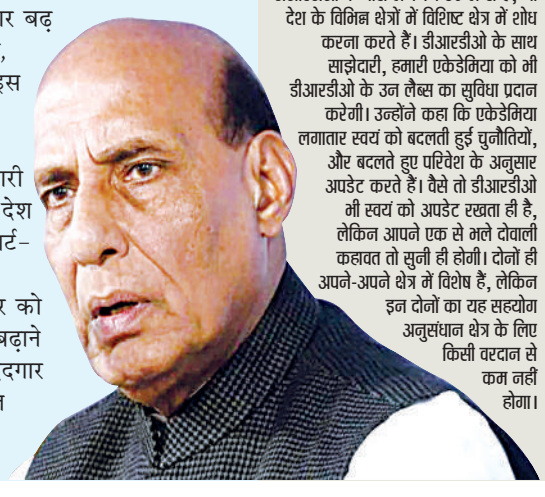

डीआरडीओ हो रहा अपडेट

भाजपा नेता ने कहा कि डीआरडीओ के पास एक बेहद उन्नत बुनियादी ढाँचा है। आज डीआरडीओ के पास लगभग 50 लैब्स हैं, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट क्षेत्र में शोध करना करते हैं। डीआरडीओ के साथ साझेदारी, हमारी एकेडेमिया को भी डीआरडीओ के उन लैब्स का सुविधा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि एकेडेमिया लगातार स्वयं को बदलती हुई चुनौतियों, और बदलते हुए परिवेश के अनुसार अपडेट करते हैं। वैसे तो डीआरडीओ भी स्वयं को अपडेट रखता ही है, लेकिन आपने एक से भले दो वाली कहावत तो सुनी ही होगी। दोनों ही अपने-अपने क्षेत्र में विशेष हैं, लेकिन इन दोनों का यह सहयोग अनुसंधान क्षेत्र के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा।

आजम खान पर फैसला, शुरू होगा चर्चाओं का सिलसिला

जिस मामले में गई थी विधायकी, उसी से हुए बरी

» उनकी सीट पर हो चुका है उपचुनाव
» अब क्या होगा, मुद्दा गरमाएगा
» अभी सदस्यता बहाली नहीं

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान को रामपुर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ी राहत दी। हेट स्पीच से जुड़े एक केस की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सपा नेता को बरी कर दिया। यह वही केस है, जिसमें उनको सजा मिली थी और इसी वजह से आजम खान अपनी विधायकी गंवा बैठे थे, रामपुर के निचले कोर्ट ने उनको 3 साल की सजा सुनाई थी। विधायकी रद्द होने के बाद उनकी सीट पर उपचुनाव भी हो गया था, अब एक बहस इस बात पर शुरू हो गई है कि आजम को सदस्यता मिलेगी या नही, यह अपनी तरह का पहला और अनूठा मामला है, इसलिए संविधान विशेषज्ञ और कानूनविद भी इस पर पशोपेश में हैं।

आजम खान को जिस आरोप के लिए 27 अक्टूबर 2022 को सजा सुनाई गई, वह दो साल से अधिक की थी। दो साल से अधिक की सजा होने पर सदस्यता खत्म करने का प्रावधान है,उस

मुकदमे में ही ये बरी हो गए, एमपी-एमएलए कोर्ट के एडीजे की अपीलेट कोर्ट ने इनको आरोपमुक्त कर दिया है, अब कानूनी पक्ष यह है कि वर्तमान में इनकी सदस्यता रद्द होने के पश्चात इनकी सीट पर मतदान भी हो चुका है और नए सदस्य ने तो शपथ भी ले ली है, कानूनी पक्ष से ये कहा जाए कि एक और अड़चन है, आजम खान के सामने. करीबन 15 साल पुराना एक मामला मुरादाबाद में है, जिसमें आजम खान को तीन साल की सजा हो चुकी है, वह मामला अभी भी इन पर भारी पड़ेगा, उस मामले को छजलैट विवाद कहा जाता है, इसमें आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने दोषी करार दिया। दोनों को दो-दो साल की सजा सुनाई गई थी और दोनों पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था,इसी की वजह से अब्दुल्ला की सदस्यता भी गई थी। यह आजम के लिए अड़चन का विषय है, अभी जिस मामले में इनकी रिहाई हुई है, वह मामला भी खुला हुआ है, वह प्रकरण उच्च न्यायालय में जा सकता है, अगर उच्च न्यायालय ने बुधवार 24 मई के आदेश पर हस्तक्षेप किया और स्टे दिया, तो अलग बात है ,हालांकि, पहली बार इस तरह की विषम परिस्थिति पैदा हुई है, लेकिन चूंकि इनको एक और प्रकरण में सजा हो चुकी है, तो सदस्यता बहाल होने का तो अभी कोई सवाल ही नहीं होता है।

कोर्ट जा सकते हैं आजम

अभी तो रामपुर से जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, उनको रोकने का कहीं से कोई सवाल ही नहीं है। अभी वह स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, क्योंकि उच्च स्तर पर कोई इंटरफेयरेंस नहीं है। दूसरी बात, आजम खान के प्रकरण में सरकार या अन्य प्रभावित पक्ष भी उच्च न्यायालय जा सकते हैं। आजम खान के समर्थक जिस तरह खुशी मना रहे हैं, वह तो राजनीतिक मामला है, लेकिन यह तो तय है कि आजम खान के लिए यह सुखद तो है ही, एक तरह से नैतिक जीत तो उनकी हुई ही है। इस तरह की स्थिति चूंकि अनूठी है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार तो करेगा ह, व्यवस्था इस पर भी आएगी कि किस तरह इस तरह की परिस्थिति से बचा जा सके, आगे के लिए मानक दृष्टिकोण और गाइडलाइन्स कोर्ट की तरफ से तो आ ही जाएंगे, लेकिन चूंकि वहां चुनाव हो चुका है, तो यह बड़ी समस्या और चिंतन का विषय होगा कि न्यायपालिका और विधायिका इस स्थिति पर क्या निर्णय लेकर आती है।

संवैधानिक संकट की स्थिति

निश्चित रूप से यह अभूतपूर्व और मौलिक प्रकरण है। इस तरह का मामला पहली बार आया है जिसमें सजा के तौर पर विधायकी गयी, उसको ऊपरी अदालत ने ही रद्द कर दिया, हलांकि, द्रष्टव्य है कि समकक्ष अदालत ने ही एक और ऐसे मामले में आजम खान को सजा हो चुकी है, तो सदस्यता का सवाल अभी नहीं है, पहली बार न्यायालय या विधायी व्यवस्था के समक्ष यह प्रश्न आया है, जहां आरोपी की सदस्यता जिस मामले में रद्द हुई है, वह सजा ही खत्म कर दी गयी है, सामान्य परिस्थितियां होतीं तो उनकी सदस्यता की बहाली का प्रश्न तो उठता ही, इस पूरे मामले में ही कई स्तर पर अभी विचार होना है कानून में जो रिक्तियां और विसंगतियां हैं, वह अभी पहली बार दिखी हैं तो सुप्रीम कोर्ट को इसे व्याख्यायित करने की जरूरत पड़ेगी,चूंकि विधायिका और न्यायपालिका दोनों ही के सामने इस तरह का सवाल पहली बार उठा है, तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही सलाह के लिए लोग देखेंगे। आपको अगर याद हो तो 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश के तहत यह व्यवस्था दी थी कि किसी को भी अगर दो या दो से अधिक साल की सज़ा होती है, तो उसकी सदस्यता स्वतः रद्द कर दी जाएगी। ये व्यवस्था भी वहीं से शुरू हुई। इस प्रश्न को लेकर फिर से मंथन वहीं से शुरू होगा ही।

2013 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला मिसाल

2013 के उस आदेश की वजह से न केवल राहुल गांधी की, बल्कि कई अन्य प्रदेशों में कई जनप्रतिनिधियों की सदस्यता गयी है। राहुल गांधी का विषय इनसे बिल्कुल अलग है, दूसरी किसी अन्य अदालत से इस तरह का आदेश या प्रारूप नहीं है, तो उनकी स्थिति अलग है, दूसरी बात यह कि वायनाड में चूंकि चुनाव नहीं हुए हैं, तो अगर ऊपरी अदालत उस आदेश को रद्द करती है, या स्टे लगाती है तो उनकी सदस्यता के रिवाइवल की स्थिति बन सकती है,सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 2013 का, वह पूरे देश में एक समान लागू होता है और कानून की तरह मान्यता रखता है. साथ ही, यूपीए सरकार का वह अधिनियम याद कीजिए, जिसमें इस सजा के विपरीत सरकार ने उसे पांच साल तक की अवधि का करने का प्रावधान किया था, माननीय राहुल गांधी ही थे, जिन्होंने कैबिनेट के अप्रूड बिल को सार्वजनिक तौर पर फाड़ दिया था, यह अलग बात है कि जिस बिल को उन्होंने फाड़, वही उनकी सदस्यता जाने का भी कारण बना, उससे न केवल राहुल सदस्यता खोने से बचते, बल्कि कई अन्य लोग भी जिनकी सजा 2 साल या 3 साल थी, उनकी भी सदस्यता जाने से बचती।

बड़े दिल से सब एक साथ आएं

» आमजन की यही पुकार : ये भारत का कार्यक्रम, सियासत को करें दूर
» सत्ता पक्ष भी झुके, विपक्ष भी हो नरम
» विपक्षी दलों को भी राजनीति करने से बचना होगा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। सही है या गलत संसद का उद्घाटन पीएम करेंग, इस पर बहस हो सकती है पर ये आमजन से चर्चा करिये तो वह तो यही कहता है कि सता पक्ष व विपक्ष दोनों को इस कार्यक्रम में मिलकर आना चाहिए, दुनिया में भारत की एकता दिखाकर मिसाल पेश करना चाहिए। अगर सचमुच में नए संसद भवन के उदघाटन समारोह के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया है, तो लोकसभा स्पीकर के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जरूर एक बार इस पर विचार करना चाहिए। उदघाटन कोई कर दे।

28 मई की उस तस्वीर में जब पूरे देश की ताकत एकजुटता के साथ दिखेगी, तो फिर भारत कितना मजबूत नजर आएगा. कल्पना कीजिए कि उस तस्वीर में राष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, बाकी सारे मंत्री होंगे और उसके साथ ही हर विपक्षी दल का प्रतिनिधित्व होगा तो फिर इस तस्वीर से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। इस पहलू को देखते हुए सरकार की ओर से भी समझदारी दिखनी चाहिए और देश के लिए

विपक्ष को हो सकता है नुकसान

विपक्षी दलों को एक बात समझनी चाहिए कि नया संसद भवन सिर्फ सरकार का नहीं है। ये देश के हर नागरिक की तरह उनका भी है, देश के तमाम दलों का है। अगर कांग्रेस और उनके साथ बाकी कई दल सिर्फ़ चुनावी नजरिए से संसद भवन जैसे मसले को मुद्दा बना रहे हैं, तो ये सारे दल भूल कर रहे हैं। भारत में लोगों के लिए भावनात्मक मुद्दे ज्यादा अहमियत रखते हैं और ज्यादातर लोग यही मानकर चलेंगे कि देश को नया संसद भवन मिल रहा है, ये राष्ट्रीय अस्मिता का विषय है। ऐसे में कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल एक तरह से अपना ही नुकसान कर रहे हैं और बीजेपी का इससे कोई नुकसान नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा फायदा ही होने वाला है।

सरकार को घेरने के लिए देश में और हैं मुद्दे

देश में कई मुद्दे हैं, जो जरूरी हैं..महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, घर का अभाव, मेडिकल सुविधाओं का अभाव समेत कई मुद्दे हैं, जिनको लेकर विपक्षी दल सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार को घेर सकते हैं, बीजेपी के खिलाफ लामबंदी कर सकते हैं। लेकिन नए संसद भवन का उदघाटन समारोह किसी भी तरह से राजनीति का मुद्दा नहीं बनना चाहिए। ये बात न तो सरकार के हित में है, न ही विपक्षी दलों के। उससे भी ज्यादा देश की एकजुटता के नजरिए से भी इससे सही संदेश नहीं जाएगा।

गौरवपूर्ण इस पल से पूरी दुनिया को ये संदेश जाना चाहिए कि जब बात राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ी हो तो यहां की सरकार विपक्षी दलों की भावनाओं को भी उतना ही महत्व देती है। इसके साथ ही कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को भी ये गंभीरता से सोचना चाहिए कि नए संसद भवन का उदघाटन कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, अगर राष्ट्रपति की जगह प्रधानमंत्री ही उस इमारत का उदघाटन कर रहे हैं तो भी ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर राजनीतिक नजरिए से लाभ-हानि सोचकर रणनीति बनाई जाए। ऐसे भी इस देश में कई मौके आए हैं, जब किसी इमारत के उदघाटन में बहुत तरह की ऊंच-नीच देखने को मिली है और ये भी सोचना होगा कि उदघाटन का अधिकार कोई संवैधानिक अधिकार नहीं होता। सैद्धांतिक तौर से ये किसी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन भी नहीं है, ये तो बस व्यवहार की बात है। कांग्रेस समेत जिन 19 दलों ने नए संसद भवन के उदघाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया है, उनमें वे सारे दल ही शामिल हैं, जो एक तरह से 2024 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ देशव्यापी स्तर पर विपक्षी गठबंधन बनाने की चाह रखते हैं। इस बहिष्कार से बीजेडी के नवीन पटनायक, वाईआरएस कांग्रेस के जगनमोहन रेड्डी, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, शिरोमणि अकाली दल ने अपने आप को दूर रखा है। यानी ये दल समारोह में शामिल होंगे। मायावती की भी ज्यादा संभावना शामिल होने की ही है, वहीं बीआरएस के प्रमुख के. चंद्रशेखर राव की ओर से भी ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं कि वे भी समारोह से दूरी ही बनाएंगे।

एक साथ खड़े हो सरकार और विपक्ष

सरकार और सभी विपक्षी दलों को ये समझना होगा कि नया संसद भवन लोकतंत्र का प्रतीक है और आने वाले सदियों-सदियों तक ये हमारी पहचान रहेगा। इसलिए दोनों ही पक्षों को बाकी मुद्दों पर राजनीति करनी चाहिए और इसे राष्ट्रीय गौरव का पल बनाने के लिए हर वो कदम उठाना चाहिए जिससे अंतरराष्ट्रीय पटल पर एक मजबूत और एकजुट भारत की छवि बनती हो। इस दिशा में सरकार को भी विपक्षी दलों से बात कर हल निकालना चाहिए। उन्हें उदघाटन समारोह में शामिल होने के लिए मनाना चाहिए तो दूसरी तरफ कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को भी अपनी जिद्द छोड़कर इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनना चाहिए। अब सब कुछ दोनों पक्षों की समझदारी और सही मायने में राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़े मुद्दे पर एकजुटता दिखाने पर टिका है।

संसद पर सिर्फ सरकार का अधिकार नहीं

अब जरा सोचिए कि संसद सिर्फ सरकार या सत्ताधारी दल से नहीं बनती है। इसके संगठन और सार्थकता में विपक्षी दलों की भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब ये कैसा लगेगा कि देश को नया संसद भवन मिल रहा है, देश को नए संसद भवन के तौर पर लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रतीक मिल रहा है और उस मौके से ज्यादातर विपक्षी दल गायब हैं या बहिष्कार मुहिम में शामिल है।

जिद... सच की

Sanjay Sharma
editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

एआई का बड़े पैमाने पर उपयोग नुकसानदेह

अभी हाल ही में खुलासा हुआ है एक खबर समाचार पत्रों व चैनलों में आई थी कि अमेरिका के रक्षा मुख्यालय के पास धमाका। वह पूरी तरह फेक थी। उसे कुछ शरारती तत्वों एआई के माध्यम से तैयार किया था। उधर लंदन में वॉल स्ट्रीट जर्नल के सीईओ काउंसिल समिट में वर्चुअल भागीदारी में प्रौद्योगिकी की आलोचना करते हुए एलन मस्क ने कहा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दोधारी तलवार बताया।

स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) कंट्रोल ड्रोन के बड़े पैमाने पर उत्पादन पर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ऐसे ड्रोन के निर्माण से भविष्य में होने वाली सैन्य झड़पें केवल ड्रोन युद्ध होंगी। उनकी यह आशंका वाजिब भी है। अभी हाल ही में खुलासा हुआ है एक खबर समाचार पत्रों व चैनलों में आई थी कि अमेरिका के रक्षा मुख्यालय के पास धमाका। वह पूरी तरह फेक थी। उसे कुछ शरारती तत्वों एआई के माध्यम से तैयार किया था। उधर लंदन में वॉल स्ट्रीट जर्नल के सीईओ काउंसिल समिट में वर्चुअल भागीदारी में प्रौद्योगिकी की आलोचना करते हुए एलन मस्क ने कहा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दोधारी तलवार बताया। मस्क ने कहा कि अगर आपके पास जिन्न है दो आपको कुछ भी दे सकता है, तो यह एक खतरा पैदा करता है। उन्होंने आशंका जताई कि दुनियाभर की सरकारें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ और बनाने से पहले हथियारों को विकसित कर सकती हैं।

ट्विटर के 51 साल के पूर्व सीईओ मस्क ने कहा कि इसलिए युद्ध के मैदान पर अधिक उन्नत हथियार होना जो किसी भी इंसान की तुलना में अधिक तेजी से प्रतिक्रिया कर सकता है, वो वास्तव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक से लैस होगा। उन्होंने कहा कि अडवांस देश और कम से कम ड्रोन क्षमता वाले देशों के बीच कोई भी भविष्य का युद्ध सिर्फ ड्रोन युद्ध ही होगा। मार्च में एलन मस्क दुनिया के उन टेक दिग्गज और सीईओ में से एक थे, जिन्होंने दुनिया से मानवता और सभ्यता के लिए गंभीर जोखिमों का हवाला देते हुए एआई के विकास में तेजी से प्रगति को रोकने का आग्रह किया था। 1000 से अधिक लोगों ने छह महीने के लिए हॉफ एआई डेवलपमेंट पत्र पर हस्ताक्षर किया था। दरअसल, तब सैन्य फ्रांसिस्को स्थित एक टेक स्टार्टअप ने अपने शक्तिशाली इंसानों जैसे चैटबॉट चैटजीपीटी-4 को जारी किया था। इसी के बाद से एआई टेक्नोलॉजी को अपनाने को लेकर टेक दिग्गजों के बीच बहस छिड़ गई थी। यह पत्र इसी घटनाक्रम के बाद जारी किया गया था। सबसे पहले सोशल मीडिया पर लोगों की राय में हेरफेर करने के लिए एआई का उपयोग करने को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बारे में कहा कि मुझे लगता है कि एआई हेरफेर के प्रभाव को कम करने के तरीके के लिए हमें इसकी तलाश की आवश्कता होगी। उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से ट्विटर पर गंभीरता से ले रहे हैं और मुझे लगता है कि हम सिस्टम में बड़े पैमाने पर हेरफेर का पता लगाने के लिए सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत कर रहे हैं।

संजय

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

कांग्रेसी अगुआई को लेकर क्षेत्रीय दलों की चिंताएं

उमेश चतुर्वेदी

कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद गैर भाजपा दलों का खुश होना स्वाभाविक है। यह बात और है कि बंगलुरू में गत 20 मई को हुए सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में यह प्रसन्नता कम ही दिखी। वहां जुटे विपक्षी नेताओं की मौजूदगी सिर्फ सांकेतिक ही नजर आई। विपक्षी राजनीति का कोई ठोस संकेत नहीं मिला। इसके बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी शिद्दत से विपक्षी एकता की कमान थाम लेने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनकी मुलाकात को इसी नजरिये से देखा जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन मुलाकातों के बावजूद कांग्रेस विपक्षी एकता के लिए अपने नेतृत्व को कुर्बान करने को तैयार होगी? कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस क्या विपक्षी गोलबंदी में उसी तरह पृष्ठभूमि में रहने को तैयार होगी, जैसे कर्नाटक चुनाव के पहले तक दिख रही थी?

दरअसल, जिस तरह नीतीश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधी मुहिम की अगुआई करने की कोशिश में जुटे हैं, उससे लगता है कि उन्होंने मोदी को सत्ता से बाहर करने का संकल्प ले लिया है। दो महीने पहले जनता दल यू की कार्यकारिणी का गठन किया था, लेकिन तब पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार केसी त्यागी को कोई जगह नहीं मिली थी। ऐसा नीतीश की मर्जी के बिना तो नहीं ही हुआ होगा। लेकिन मोदी विरोधी अभियान छेड़ने के बाद उन्हीं केसी त्यागी की उपयोगिता नीतीश कुमार को समझ आने लगी है। इसकी वजह है, केसी त्यागी का तमाम पार्टियों के नेताओं से सुमधुर रिश्ता रहना। नीतीश को उम्मीद है कि विपक्षी लामबंदी में केसी त्यागी के राजनीतिक रिश्ते उनके लिए कारगर हो सकते हैं। नीतीश की कोशिशों से 1987 के विपक्षी अभियानों की याद आना स्वाभाविक है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी बोफोर्स दलाली के आरोपों से जूझ रहे थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह की अगुआई में अरुण नेहरू, रामधन, आरिफ मोहम्मद खान और सतपाल मलिक ने कांग्रेस से अलग राह अपना ली थी। तब नीतीश कुमार, शरद यादव के राजनीतिक शागिर्द माने जाते थे, उन दिनों शरद के राजनीतिक बॉस देवीलाल का हरियाणा की सत्ता पर कब्जा था। तब उन्होंने राजीव विरोधी परिवर्तन रथ चला रखा था। आंध्र प्रदेश के नेता नंदमुरि तारक रामाराव ने भी तेलुगू देशम पार्टी के बैनर तले यात्रा निकाल रखी थी। साल 1987 में समूचे विपक्ष को एक होने का मौका इलाहाबाद उपचुनाव से मिला

था, जिसमें राजीव के लेफ्टिनेंट रहे वीपी सिंह उतरे थे और कांग्रेस के उम्मीदवार और उत्तर प्रदेश सरकार के तत्कालीन कांग्रेसी मंत्री सुनील शास्त्री को हरा दिया था। नीतीश भी इन दिनों कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन वीपी सिंह जैसी एकता होती नजर नहीं आ रही है। बीस मई को बंगलुरू में हुए सिद्धारमैया सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में आम आदमी पार्टी को बुलावा नहीं मिला। जिस ममता बनर्जी को मिला, उन्होंने खुद आने की बजाय अपनी एक सांसद को भेज दिया। विपक्षी राजनीति के कद्दावर चेहरे शरद पवार भी बंगलुरू में नजर नहीं आए। के. चंद्रशेखर राव को भी निमंत्रण नहीं था। आंध्र के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी को कांग्रेस से बुलावा मिलना ही नहीं था। विपक्षी राजनीति के एक और अहम चेहरे नवीन पटनायक भी वहां नहीं पहुंचे। जाहिर है कि विपक्षी एकता बनने के पहले ही बिखर गयी। साल 2018 में हुए एचडी कुमार स्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में भी विपक्षी दिग्गज जुटे थे, लेकिन अगले ही साल हुए लोकसभा चुनावों में विपक्ष की मौजूदगी खास नहीं रही। इस बार तो समूचा विपक्ष रहा भी नहीं, ऐसे में विपक्षी एकता की कैसे उम्मीद की जा सकती है? विपक्षी राजनीति के दिग्गजों में कांग्रेस के साथ दिखने में हिचक की वजह है मुस्लिम वोट बैंक। कर्नाटक में जिस तरह कांग्रेस का मुस्लिम वोटरों ने एकमुश्त समर्थन किया है, उससे कई भाजपा विरोधी क्षेत्रीय दल सशंकित हैं। विशेषकर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं की चिंता सबसे ज्यादा बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में जहां करीब 18 प्रतिशत मुस्लिम वोटर हैं, वहीं पश्चिम बंगाल में करीब 30 प्रतिशत मुस्लिम मतदाता हैं।भारतीय राजनीति में अतीत में इस वोट बैंक पर सिर्फ कांग्रेस का ही असर होता था। लेकिन राम मंदिर आंदोलन और सामाजिक न्याय की राजनीति के दौर में मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस से दरकता हुआ हर प्रदेश में उन दलों के साथ जुड़ता गया, जिनसे उन्हें सांप्रदायिकता विरोध के नाम पर भाजपा को हराने की उम्मीद थी। मसलन, उत्तर प्रदेश में साल 2012 तक समाजवादी पार्टी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस व दिल्ली में आम आदमी पार्टी। अभी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में कम से कम विधानसभा चुनावों तक खतरा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आगामी लोकसभा चुनावों में यह वोट बैंक आप की बजाय कांग्रेस की ओर कर्नाटक की तरह लौट सकता है।

गतिशील आर्थिकी के कारकों का मिले संबल

सुबीर रॉय

नये वित्त वर्ष में भारत अपनी अर्थव्यवस्था में वह तरक्की बनाना चाहता है जो वक्ती खुशनुमा अहसास न देकर स्थायित्व वाली हो। यह इसलिए कि भारत को विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाने की राह में कई ऐसे मुकाम आएंगे, जिनकी प्रकृति विकास दर को नीचे खींचने की होगी, लिहाजा इनका उपाय करना जरूरी है। सरकार के अपने शब्दों में 'नीचे खिसकने का जोखिम, ऊपर उठने का मौका।' सरकार ने अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.5 प्रतिशत रखने की आकांक्षा दोहराई है, भले ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने अपने आकलन में मौजूदा वित्त वर्ष में इसको 20 बिंदु घटाकर 5.9 फीसदी दर्शाया है। भारत को लेकर विश्व बैंक का आकलन इससे कुछ बेहतर यानी 6.3 फीसदी है। आशा को संयमित रखने के पीछे कारण कई हैं। सबसे पहला यह कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की दर फिलहाल अधोन्मुख है। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में, औसत आर्थिक विकास दर 3 प्रतिशत रहने का आकलन है, जो कि पिछले साल के 2.8 फीसदी से कुछ ही अधिक है।

वैश्विक आर्थिक विकास दर निस्तेज रहने के पीछे मुख्य कारण है तेल की कीमतें। तेल उत्पादक संघ ने उत्पादन घटा दिया है, जिसकी वजह से कीमतें अप्रैल माह में मार्च के न्यूनतम से अधिक रहीं। जब तक यूक्रेन-रूस युद्ध चलता रहेगा, विश्वभर में वस्तुओं के दामों में उतार-चढ़ाव बना रहेगा क्योंकि तेल उत्पादक संघ के 'आपूर्ति खेल' से तेल की कीमतें एक बिंदु से नीचे नहीं जा पा रहीं। वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव के पीछे दूसरी बड़ी वजह है अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने के बाद से ऋण-प्रणाली पर पड़ा प्रभाव और जिससे बनी उथल-पुथल ने दुनियाभर को चपेट में ले रखा है। यह स्थिति विदेशी निवेश के आसान प्रवाह में अड़चन पैदा कर रही है। जोखिम उठाने और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में निवेश करने की बजाय अमेरिकी सरकार की निवेशकों को सरकारी प्रत्यभूतियों में धन लगाने पर अधिक प्रोत्साहन राशि देने वाली नीति से मदद नहीं मिलने वाली। लेकिन सुदूर देशों में उठती इन लहरों की मार का असर ज्यादा रहने की बजाय, हमारे अपने देश की अर्थव्यवस्था को जो सबसे बड़ी अनिश्चितता और जोखिम दरपेश है, वह है आगामी मानसून की दशा।

देश के कुछ अंचलों में प्रचंड गर्मी की वजह से पहले ही सब्जियों के दामों में बहुत तेजी आई है। खाद्य वस्तुओं की कीमतें भी ऊंची हैं और यदि बारिश कम हुई तो स्थिति क्या होगी, कोई पता नहीं। पिछले कुछ सालों के आंकड़ों से देखा जाए तो परिस्थितियां अल-नीनो की चोट का इशारा कर रही हैं, जिसकी वजह से देश में मानसून चक्र असामान्य हो सकता है। एक तो वैश्विक अर्थव्यवस्था की मौजूदा चाल से कोई सहायता न मिलने और दूसरा कृषि उत्पादन क्षीण रहने की आशंका से आर्थिक वृद्धि दर में और कमी आने के कयास से, तमाम नजरें और उम्मीदें अब उत्पादन और सेवा क्षेत्र की कारगुजारी पर टिकी हुई हैं। अब तक तो, बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश ने बाजार मांग के अनुरूप परिणाम दिया है, लेकिन यह सफर आगे भी यूं ही जारी रहेगा, उम्मीद कम है। निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़?ावा देने के सरकार के प्रयासों से उम्मीद बंधती है कि उलीकी गई आर्थिक वृद्धि के लिए जो अवयव जरूरी हैं, वे बन पाएंगे।

आर्थिकी में निजी क्षेत्र का निवेश फिलवक्त बहुत महत्व रखता है क्योंकि उपभोक्ताओं की मौजूदा व्यय-समर्था से अर्थव्यवस्था में वांछित परिणाम नहीं मिल पाए। चाहे यह आवास हो या वाहन या फिर मोबाइल फोन की खरीदारी, उपभोक्ता बाजार की चोटी इन श्रेणियों में काफी मांग देखी जा रही है, जबकि बाकी वस्तुओं की मांग में भारी कमी बनी हुई है। नतीजतन, कोविड महामारी के बाद वाले काल में, विवेकाधीन व्यय श्रेणी में तो मांग देखी जा रही है किंतु आवश्यक वस्तुओं की खपत में कमी निरंतर जारी है। इसका पता रोजमर्रा की वस्तुएं बनाने वाली कंपनियों की कमजोर बिक्री से साफ लग जाता है। उपभोक्ता किसी वस्तु की खरीदारी तभी कर रहा है जब उसको लिए बिना कोई चारा नहीं। अधिसंख्य जनता की इस क्षीण खरीदारी-क्षमता के अलावा निजी क्षेत्र की मुश्किलों को जिसने बढ़ाया है, वह है वित्तीय संस्थानों द्वारा कर्ज पर लागू मौजूदा ऊंची ब्याज दर। उन्हें भी यह इसलिए करना पड़ा क्योंकि मुद्रास्फीति को 4 फीसदी से नीचे रखने का ध्येय को पाने को रिजर्व बैंक नियामक दर को ऊपर उठा देता है। पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए, खासकर जब अधिकांश उपभोक्ता वस्तुओं की मांग काफी कम हो, ऐसे में कंपनियों-व्यापारियों को ऊंची दर पर उधार देने वाले उपाय से शायद ही कोई फायदा हो।

इस स्थिति में, आर्थिक विकास दर 6.5 फीसदी रखने के ध्येय को धक्का लगने का जोखिम न्यूनतम रहे, देश के नीति-निर्धारिकों के पास कौन से विकल्प बचते हैं सिवाय कुछ सुधार करने के? सर्वप्रथम, कोविड महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में जिस तरह अंग्रेजी अक्षर के-आकार वाला सुधार पैटर्न बनने लगता था, वह जाता रहा, जिसकी वजह से चोटी के कुछ अमीरों की आय में गैर-अनुपातीय वृद्धि हुई, उसका उपाय करना होगा। जनसंख्या के निचले वर्ग की समुचित क्रय-शक्ति बनाना जरूरी है ताकि ग्रामीण इलाके में आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी होने से, इन्हें बनाने वाली कंपनियों का धंधा भी फले-फूले। गरीबों की आय में अतिरिक्त मदद उपायों से बढ़ोतरी करने की आवश्यकता आगे भी बनी रहेगी।

खाना सिखाएं

छोटा बच्चा मां के दूध से पेट भरता है। धीरे धीरे वह हल्का भोजन भी करने लगता है। लेकिन आप बच्चे को खुद से खिलाते हैं। हालांकि एक उम्र के बाद बच्चे को स्वयं भोजन करना सीखना चाहिए। इसके लिए उन्हें चम्मच पकड़ना सिखाएं। कैसे रोटी तोड़ कर खाई जाती है या दाल व चावल किस तरह से मुंह तक लाया जाता है, यह सिखाएं। उनके सामने खुद खाना खाएं और उन्हें भी खाने का तरीका कॉपी करने के लिए कहें।

बात करना सिखाएं

एक साल का बच्चा बोलना शुरू कर देता है। बोलना सिखाने के लिए यह सबसे सही समय है। बच्चे दूसरे की बातों को सुनकर उसके बोलने की कोशिश करने लगते हैं। आसपास की चीजों को अपनी तोतली आवाज में अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ऐसे में अभिभावकों को बच्चे को बोलना सिखाने के लिए साधारण और सरल शब्दों का उपयोग करना चाहिए। जो आप उन्हें बोलना सिखाना चाहते हैं, उसे खुद भी बोलें ताकि बच्चा आपको कॉपी करके बोलना सीखें।

खेल-खेल में सिखाएं बच्चे को काम की बात

बच्चे के जन्म के बाद माता पिता की चिंता उसके लालन पालन से लेकर भविष्य को संवारने में रहती है। बच्चा स्वस्थ रहे और उसका विकास हो, इसके साथ ही समाज में रहने योग्य बन सके, इसके लिए माता पिता बचपन से ही बच्चे को सीख देने लगते हैं। जब बच्चा बोलना शुरू करता है, तो अभिभावक उसे रिश्ते को संबोधित करना सिखाते हैं। धीरे धीरे दैनिक जीवन से जुड़ी बातें सिखाते हैं। जैसे ब्रश करना, बड़ों को प्रणाम करना, गलती पर माफी मांगना, किसी चीज को पकड़ना, लोगों से संवाद करना आदि। 4-5 साल की आयु के बाद बच्चे को सिखाना आसान होता है, क्योंकि वह आपकी बाते समझने लगता है। लेकिन जब बच्चा महज एक डेढ़ साल का होता है, तो उसे कुछ सिखाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे में छोटे बच्चे को कुछ सिखाने के लिए आसान और मजेदार तरीके अपनाएं। खेल-खेल में उन्हें जीवन का पाठ पढ़ाएं।

घुलना-मिलना सिखाएं

जब तक बच्चा माता पिता की गोद में होता है, वह सिर्फ अपने परिवार को ही पहचानता है। किसी बाहरी के गोद में लेने या सामने आने पर अक्सर बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। 1 साल का बच्चा समझने लगता है और उसे अपने परिवार व बाहरी लोगों का फर्क पता चलने लगता है। इस उम्र में बच्चे को दूसरों से घुलना मिलना सिखाएं। इसके लिए उन्हें पार्क लेकर जाएं ताकि वह अन्य बच्चों के संपर्क में आए और समाज में कैसे रहना है, ये सीखे। इससे बच्चे के बर्ताव में भी परिवर्तन आएगा।

अपनी बात कहना सिखाएं

छोटा बच्चा भूख प्यास लगने पर भी रोता है और मल मूत्र होने पर भी रोता है। लेकिन जब वह समझने लगे तो उसे सिखाएं कि भूख लगने पर उसे खाना मांगना है। वहीं अगर उसे मल मूत्र त्याग करना है तो किस तरह वह माता पिता को बता सकता है। इसके लिए उन से थोड़ी थोड़ी देर में पूछें कि क्या उन्हें भूख लगी है, या क्या उन्हें टॉयलेट जाना है। इस पर बच्चे की प्रतिक्रिया आने दें। धीरे धीरे वह खुद आपको बताना शुरू कर देंगे।

हंसना मना है

पति- ये सब्जी जो तुमने बनाई है इसका क्या नाम है? पत्नी- क्यों पूछ रहे हो? पति- मुझे भी तो ऊपर जाकर जवाब देना है जब वो पूछेंगे- क्या खाकर मरे थे? पति की इस बात को सुनकर बीवी ने उसकी बेलन से कुटाई कर दी।

टीचर- मोटू एक सवाल का जवाब दो मोटू- जी टीचर, टीचर- क्लास में लड़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए? मोटू- क्योंकि पता नहीं एग्जाम में कब किसके पीछे बैठना पड़ जाए। मोटू की बात सुनकर टीचर भी सोच में पड़ गई।

पप्पू काफी देर से अपने मैरिज सर्टिफिकेट को घूर कर देख रहा था! उसकी पत्नी सोनी बोली- इतनी देर से इसे क्यों घूर रहे हो? पप्पू- इसकी एक्सपायरी डेट ढूंढ रहा हूं।

पत्नी पति से- कहां पर हो आप? पति- स्कूटर से गिर गया हूं, एक्सीडेंट हो गया है और हॉस्पिटल जा रहा हूं.. पत्नी घबराते हुए बोली- ध्यान रखना जरा, टिफिन टेढ़ा ना हो जाए, वरना दाल गिर जायेगी।

पति (पत्नी से)- जरा, पानी पीला दो, पत्नी- क्या हुआ प्यास लगी है? पति (गुस्से से)- नहीं गला चैक करना है, कि कहीं से लीक तो नहीं है!

कहानी | शेर और चूहा

एक बार की बात है, किसी जंगल में एक चूहा रहता था। एक दिन जब वो अपनी बिल की तरफ लौट रहा था, तो उसने एक गुफा में एक शेर को आराम करते देखा। शेर को मजे में सोते हुए देख चूहे के मन में शरारत सूझी। चूहा शेर की गुफा में जा घुसा और शेर के ऊपर चढ़ गया। वह शेर के ऊपर खूब उछल-कूद करने लगा और उसके बाल खींचने लगा। चूहे की शरारतों से शेर की नींद खुल गई और उसने चूहे को अपने नुकीले पंजों में दबोच लिया। चूहे ने जब शेर के पंजे में खुद को पाया, तो वो समझ चुका था कि शेर के गुस्से से अब उसे कोई नहीं बचा सकता और आज उसकी मौत तय है। चूहा बुरी तरह डर गया और रो-रोकर शेर से विनती करने लगा कि शेर जी, मुझे मत मारो, मुझसे भूल हो गई, मुझे जाने दो। अगर आज आप मुझे जाने देंगे, तो मैं आपके इस उपकार के बदले भविष्य में जब भी आपको किसी मदद की जरूरत होगी, मैं आपकी मदद करूंगा। चूहे की बातें सुनकर शेर की हंसी निकल गई। शेर ने कहा कि तुम तो खुद इतने छोटे हो, मेरी मदद क्या करोगे? चूहे की विनती सुनकर शेर को उस पर दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहे ने शेर को धन्यवाद बोला और वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद जब शेर खाने की तलाश में इधर-उधर घूम रहा था, तभी अचानक किसी शिकारी के फैलाए जाल में फंस गया। शेर ने खुद को जाल से निकालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन निकल नहीं पाया। काफी देर कोशिश करने के बाद शेर ने मदद के लिए दहाड़ लगानी शुरू की। उसी वक्त वो चूहा उधर से गुजर रहा था कि उसने शेर की दहाड़ने की आवाज सुनी। वो भागकर शेर के पास गया और शेर को जाल में फंसा देख चौंक गया। उसने बिना देर करते हुए अपने नुकीले दांतों से जाल को काटना शुरू किया और कुछ ही देर में उसने पूरे जाल को काटकर शेर को आजाद कर दिया। चूहे की इस मदद से शेर की आंखें भर आईं और नम आंखों से शेर ने चूहे को धन्यवाद किया और दोनों वहां से चले गए। फिर शेर और चूहा अच्छे दोस्त बन गए।

7 अंतर खोजें

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष

आज कुछ लोगों की मदद से आपके काम पूरे होंगे। आपको कोई अच्छी खुशखबरी मिलेगी। पार्टनर आपकी हर बात को समझने की कोशिश करेंगे।

तुला

आज सभी काम मन-मुताबिक पूरे होंगे, लेकिन जरूरत से ज्यादा एकाग्रता के कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है। आप किसी सामाजिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं।

वृषभ

वित्तीय रूप से यह अच्छा दिन नहीं है। बेतरतीब निवेश समस्याएं पैदा कर सकता है। किसी जानकार से सलाह लेना बेहतर रहेगा। आप अपने जीवनशैली में कुछ बदलाव लाएंगे।

वृश्चिक

स्वास्थ्य संदर्भ में यदि कोई बीमारी पहले से चली आ रही है तो वह इस सप्ताह बढ़ सकती है, अतः पहले से ही सावधानी बरतें। धन के मामले में दिन सामान्य रहेगा।

मिथुन

आज आपके अधूरे काम पूरे हो जायेंगे। आपको कुछ नए मौके मिलने की संभावना बन रही है। प्रेम-प्रसंग में सब कुछ अच्छा रहेगा। आपका मन प्रसन्न रहेगा।

धनु

आज दोस्ती के रिश्ते मजबूत होंगे। कारोबारियों को उम्मीद से ज्यादा लाभ होगा। ऑफिस में अपनी राय रखने का पूरा मौका मिलेगा।

कर्क

आज व्यवसायिक दृष्टि से सकारात्मक विकास संभव है और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे अच्छा प्रदर्शन करेंगे।

मकर

परीक्षा या प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र सफलता प्राप्त करेंगे। अगर कोर्ट में कोई संपत्ति संबंधी मामला है तो वह आपके पक्ष में जाएगा।

सिंह

आज आपको पुरानी बातों के झंझट में पड़ने से बचना चाहिए। छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने से कुछ लोग आपका विरोध कर सकते हैं।

कुम्भ

आज आपकी कई योजनाएं समय से पूरी होंगी। परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी। अपनी बढ़ी ऊर्जा से आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे।

कन्या

आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। आप दूसरों पर अपने शब्दों से प्रभाव डालेंगे। लेकिन आपकी सेहत आपको सहयोग नहीं करेगी।

मीन

यात्राएं अधिक हो सकती हैं। आपको अपने वरिष्ठों और आधिकारिक से सहायता और पुरस्कार प्राप्त हो सकते हैं। आप अपने कार्य स्थल पर प्रशंसा के पात्र रहेंगे।

बॉलीवुड | गणशप

प्रियंका को हाई स्कूल की फोटोज को जलाने का आज भी मलाल है

ग्लोबल स्टार बन चुकीं एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जोनस हर दिन सुर्खियों में बनी रहती हैं। उन्होंने हिन्दी सिनेमा से लेकर हॉलीवुड तक में अपना ऐसा जादू चलाया कि दुनियाभर के लोग उनके दीवाने हो गए। हालांकि, फिल्मों के अलावा प्रियंका इन दिनों अपने बेबाक बयानों और निजी जिंदगी की वजह से भी लगातार चर्चा में हैं। अब फिर से उन्होंने फक ऐसा खुलासा किया, जिसने सबके होश उड़ा दिए।

प्रियंका ने हाल ही में बताया है कि उन्होंने अपने हाई स्कूल की बहुत सारी तस्वीरों को जला दिया था, जिसे लेकर आज भी उन्हें काफी पछतावा है। प्रियंका ने अपने हालिया इंटरव्यू में उस दौर के फैशन को लेकर बात की। एक्ट्रेस ने बताया कि जब वह हाई स्कूल में थीं, तब उन्होंने उस वक्त की ज्यादातर फोटोज को जला दिया था। प्रियंका ने 2000 के दशक की शुरुआत की बात की।

प्रियंका का कहना है कि ने अपने हाई स्कूल की फोटोज को जला दिया, क्योंकि वह उन्हें देखकर बहुत शर्मिंदा होती थीं। एक्ट्रेस ने कहा उस वक्त आई लाइनर, हाइलाइट्स, आई शैडो, चेन ड्रेस, लो वेस्ट जींस और थोंग्स फैशन में थे। हर चीज के साथ ओवरबोर्ड जोन का चलन था। ऐसे में एक्ट्रेस इतनी ज्यादा सोच में डूब गई कि उन्होंने उन फोटोज को ही जला दिया।

किताब लिखते समय पड़ी फोटोज की जरुरत

प्रियंका ने आगे बताया कि उन्हें बाद में इन फोटोज की जरूरत पड़ी और तब उन्हें उस समय जलाई गई तस्वीरों पर पछतावा हुआ। एक्ट्रेस ने कहा कि वह जब अपनी किताब लिख रही थीं तो उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें वो फोटोज नहीं चलानी चाहिए थीं, क्योंकि अब वह अपनी किताब उस दौर की पुरानी तस्वीरें दिखा सकती थीं। दूसरी ओर प्रियंका के वर्क फ्रंट की बात करें तो हाल ही में वह द रूसो ब्रदर्स की सीरीज सिटाडेल में नजर आईं। इस सीरीज में रिचर्ड मैडेन के साथ देखा जा रहा है। इसमें एक्ट्रेस का एक्शन वाला दमदार अंदाज देखने को मिला। अब जल्द ही प्रियंका लव अगेन और जी ले जरा टाइटल से बन रही फिल्मों में भी नजर आने वाली हैं।

बॉलीवुड | मन की बात

फिल्में लोगों में एकता और प्यार को बढ़ावा देने वाली बनें : नवाजुद्दीन

अ सुदीप्तो सेन के निर्देशन में बनी फिल्म द केरल स्टोरी सिनेमाघरों में धुआंधार कमाई कर रही है। वहीं कुछ जगहों पर फिल्म को विवादों के चलते बैन भी झेलना पड़ा। अनुराग कश्यप ने हाल ही में फिल्म को लेकर सपोर्ट करते हुए ट्वीट किया था और अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बैन को लेकर अपना रिएक्शन दिया है। हाल ही में अनुराग कश्यप ने फिल्म पर बैन के खिलाफ़ ट्वीट किया था जिसमें लिखा था, आप फिल्म से सहमत हैं या नहीं, यह प्रोपेगेंडा हो, काउंटर प्रोपेगेंडा हो, आपत्तिजनक हो या नहीं, इस पर बैन लगाना गलत है। कोई भी फिल्म या नॉवल जो किसी को हर्ट करे वो गलत है। जब नवाजुद्दीन को अनुराग कश्यप के इस ट्वीट के बारे में बताया गया तो एक्टर फिल्ममेकर से सहमत नजर आए। उन्होंने एक न्यूज पोर्टल से बातें करते हुए कहा- कोई भी फिल्म या नॉवल जो किसी को हर्ट करे वो गलत है। उन्होंने कहा कि हम फिल्में ऑडियंस या उनकी भावनाओं को हर्ट करने के खयाल से नहीं बनाते। उन्होंने कहा- फिल्में लोगों में सामाजिक एकता और प्यार को बढ़ावा देनेवाली हो। उन्होंने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे बढ़ाएं। उन्होंने कहा, अगर किसी फिल्म में लोगों के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की क्षमता हो तो ये बहुत गलत है। उन्होंने कहा-हमें इस दुनिया को जोड़ना है। सुदीप्तो सेन के निर्देशन में बनी फिल्म द केरल स्टोरी सिनेमाघरों में धुआंधार कमाई कर रही है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस फिल्म पर लगाए बैन के बाद पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इसे हटाने का आदेश दिया। हालांकि, कई सिनेमाघर अभी भी इस फिल्म को दिखाने से हिचक रहे हैं। केरल में भी इस फिल्म को लेकर विरोध जैसा माहौल दिखा, क्योंकि इसे काफी कम जगहों पर रिलीज किया गया था। फिल्म को लेकर जो माहौल बना था उसे देखकर लोग भी कम निकल रहे थे। ट्रेलर रिलीज के साथ ही विवादों से घिरी इस फिल्म के रिलीज के साथ ही पश्चिम बंगाल में बैन लगा दिया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद फाइनली सिंगल स्क्रीन पर फिल्म प्रदर्शित की जा रही है और इसे ऑडियंस का अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है।

ओटीटी पर दस्तक देगी शाहिद की ब्लडी डैडी

शाहिद कपूर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ब्लडी डैडी को लेकर लाइम लाइट में बने हुए हैं। एक बार फिर वह इस फिल्म में एक्शन मोड में दिखाई देंगे। ब्लडी डैडी का ट्रेलर लॉन्च हो चुका हैं। इस दौरान अभिनेता ने अपने फिल्म की ओटीटी रिलीज के बारे में खुलकर बात की है, साथ ही इस फिल्म को लेकर निर्देशक अली ने कहा भी इसकी काफी तारीफ की है। फिल्म 9 जून को जियो सिनेमा पर रिलीज हो रही है।

ट्रेलर में देखा जा सकता है कि शाहिद कपूर सूट-बूट में धांसू एंट्री करते हैं और लोगों को धोना शुरू कर देते हैं। इसके बाद रोनित रॉय और संजय कपूर की झलक भी दिखाई देती है, जो इस फिल्म में विलेन के किरदार में दिखने वाले हैं। वही, ट्रेलर में डायना पेंटी भी हैं। ब्लडी डैडी का ट्रेलर मसालेदार हैं, जो वास्तव में फिल्म देखने के लिए एक्साइटमेंट बढ़ाता है। शाहिद कपूर ने बताया कि ब्लडी डैडी को ओटीटी रिलीज के लिए डिजाइन किया गया था। एक्टर ने कहा कि इसे कभी सिनेमाघरों में रिलीज करने के प्लान से तैयार नहीं किया गया था। यह कुछ ऐसा है, जिसकी हमने तीन साल पहले योजना बनाई थी कि इसे ओटीटी पर रिलीज करेंगे। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि हम इसे सिनेमाघरों में रिलीज क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने इसे ओटीटी के लिए ही बनाया है। एर्टर ने आगे कहा किया कि कई लोगों ने उन्हें बुलाया था और उन्हें सिनेमाघरों में अपनी फिल्म रिलीज करने की सलाह दी थी। फिल्म देखने के बदलते माध्यम के बारे में बात करते हुए शाहिद ने कहा, यह शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी थी। घर पर फिल्म देखना एक आरामदायक अनुभव है और थिएटर जाना एक इवेंट एक्सपीरियंस है, जहां आप थिएटर जाते हैं और परिवार के साथ एक दिन बाहर बिताते हैं।

जज और वकील क्यों पहनते हैं काले कोट? ये शौक नहीं बल्कि मजबूरी है

सड़क पर चलते हुए अगर आपको काला कोट-पैंट और सफेद शर्ट पहने कोई व्यक्ति नजर आ जाए तो आप तुरंत ही समझ जाएंगे कि वो एक वकील है फिल्मों में या असल जिंदगी में आपने कोर्ट के जज को भी काले रंग की ही पोशाक पहने देखा होगा। पर क्या आप ये जानते हैं कि आखिर जज और वकील काले ही रंग का कोट क्यों पहनते हैं, किसी और रंग का क्यों नहीं? आज हम इसी सवाल का जवाब आपको देने जा रहे हैं। जज और वकील का काला कोट किसी फैशन की निशानी नहीं है। कई कारणों के चलते उनकी ड्रेस ऐसी हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार काला रंग अनुशासन, आत्मविश्वास और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। साथ ही सफेद रंग शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक होता है। ऐसे में जब वकील और जज काला कोट और सफेद शर्ट पहनते हैं, तो वो भी शक्ति, अनुशासन और पवित्रता की मूरत बन जाते हैं और उनसे उम्मीद की जाती है कि वो बिना गलत का साथ दिए, सच के साथ खड़े रहेंगे और कानून को जीत दिलवाएंगे। काले रंग का दृष्टिहीनता का प्रतीक भी मानते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि कानून अंधा होता है, बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए वकील और जज काला कोट पहनते हैं। दूसरा कारण ये है कि काला कोट वकीलों और जज को अन्य प्रोफेशन के लोगों से अलग दर्शाता है। ट्रेन में आप अगर चल रहे हैं और आपने काले कोट पहने किसी व्यक्ति को अगर देखा तो आपको सबसे पहले टिकट चेकर का ही ध्यान आएगा पर सड़क पर निकल जाइए तो काले कोट वाले व्यक्ति को देखकर आपको वकील ही ध्यान में आएगा। इसके अलावा साल 1961 में एडवोकेट एक्ट नियम बना था जिसके तहत वकीलों को काला कोट पहनना अनिवार्य कर दिया गया।

अजब-गजब | बाइक और कार नहीं रखते यहां के लोग, हर साल आते हैं लाखों पर्यटक

इस सबसे खूबसूरत गांव में नहीं हैं सड़कें

गांव का नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने चारों तरफ फैली हरियाली की तस्वीरें उभरने लगती है। जिससे ऐसा लगता है कि गांव बेहद खूबसूरत होते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे दुनिया का सबसे खूबसूरत गांव माना जाता है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस गांव में ना तो सड़कें है और ना ही किसी के पास कोई वाहन। ये बात यकीनन आपको हैरान कर रही होगी तो फिर इस गांव में लोग आते जाते कैसे हैं। तो चलिए आपके इस गांव के बारे में पूरी जानकारी देते हैं।

दरअसल, यूरोपीय देश नीदरलैंड में एक ऐसा गांव है जिसे दुनिया का सबसे खूबसूरत गांव माना जाता है। 'गिएथूर्न' नाम के इस गांव में हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। इस गांव को दक्षिण का वेनिस भी कहा जाता है क्योंकि यहां ये बेहद खूबसूरत है। यहां साल भर पर्यटकों की भीड़ रहती है। इस गांव की खूबसूरती देखकर आपका यहां से वापस आने का मन नहीं करेगा। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरा गांव नहरों से घिरा हुआ है। इस गांव में आपको एक भी गाड़ी या बाइक देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि इस गांव में एक भी सड़क ही नहीं है इस गांव में बाइक या गाड़ियां न होने की वजह से यहां के लोग नाव से चलते हैं। क्योंकि पूरे गांव में गलियों की बजाए नहरें बहती हैं। इन नहरों में इलेक्ट्रिक मोटर से नाव चलती हैं और कम शोर होने की वजह से लोगों को शिकायत भी नहीं रहती है। नहरों के एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए नहर के ऊपर लकड़ी के पुल बनाये गए हैं।

बताया जाता है कि साल 1170 यहां एक भयंकर बाढ़ आई थी, जिससे यहां इतना पानी आ गया। उसके बाद साल 1230 में इस गांव की स्थापना हुई। जब लोग यहां रहने आये तो उन्हें यहां पर बहुत सारे जंगली बकरियों के सींग मिले जो संभवतः साल 1170 की बाढ़ में बहकर यहां पहुंच गई थीं। शुरुआत में इस जगह को 'गेटेनहॉर्न' नाम से जानते थे। जिसका मतलब बकरियों के सींग होता है, जो बाद में जाकर 'गिएथूर्न' हो गया। गांव में इन नहरों के बनने के पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, जो कि अनजाने में हुआ था। बताया जाता है कि साल 1170 की बाढ़ के बाद जब लोग यहां रहने लगे तो बाढ़ के कारण इस जगह पर बहुत मात्रा में पिट जमा हो गई। बता दें कि पिट एक तरह की दलदली मिट्टी और वनस्पतियों का मिश्रण होता है, जिसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां आकर बसे लोग इस पिट के इस्तेमाल के लिए जगह-जगह उसकी खुदाई करने लगे। इस खुदाई के चलते कई सालों में यहां पर नहरों का निर्माण हो गया।

मोदी सरकार के नाकामी-बदहाली के नौ साल : कांग्रेस

लोगों को महंगाई, बेरोजगारी और तानाशाही फैसलों की मार झेलनी पड़ी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने केंद्र की सत्ता में आज अपने 9 साल पूरे कर लिए हैं। कांग्रेस ने इसे नाकामी के 9 साल बताया है। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें मोदी सरकार के 9 साल का जिक्र किया गया है। कांग्रेस ने बेरोजगारी से लेकर महंगाई और बाकी तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है और कहा है कि बदहाली के 9 साल पूरे हो गए हैं।

कांग्रेस की तरफ से किए गए ट्वीट में लिखा गया है। आज मोदी सरकार को 9 साल हो गए। ये नाकामी के 9 साल हैं। देश की बदहाली के 9 साल हैं। इन 9 वर्षों में लोगों को महंगाई, बेरोजगारी और तानाशाही फैसलों की मार झेलनी पड़ी। जुमलों के दम पर सत्ता में आई मोदी सरकार ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया।

बस तारीख पर तारीख देते रहे। जैसे- 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा,2022 तक सबको घर देने का वादा, कालाधन लाकर 15 लाख देने का वादा, हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा...ये तो बानगी भर है, इनके जुमले गिनने बैठें तो गिनते हुए कई दिन बीत जाएं।

ईडी-सीबीआई का डर

कांग्रेस ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर लिखा, कोई आवाज उठाए उसे दबा दो, कुचल दो, जेल में ठूंस दो, बुलडोजर चला दो। इडी, सीबीआई का डर दिखाओ। कहीं सरकार न बने तो पैसे के दम पर सत्ता खरीद लो और लोकतंत्र की हत्या कर दो।

जीएसटी से लेकर अग्निवीर तक का जिक्र

कांग्रेस ने कहा, मोदी ने अपने वादे तो पूरे नहीं किए, इसके उलट अपनी नासमझी से देश को आफत में डाल दिया। नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, बैंक की लाइनों में लोगों की मौत हुइ। कौन भूल सकता है उस भयावह मंजर को. गब्बर सिंह टैक्स से व्यापारी तबाह हैं। आए दिन इसका विरोध होता है, लेकिन सुनने वाला मोर को दाने देने में व्यस्त रहे तो लोग क्या करें। अग्निवीर के फैसले ने युवाओं के सपनों को कुचल दिया, जब वो विरोध में उतरे तो उन्हें धमकाया गया कि उनका भविष्य चौपट कर दिया जाएगा, हा,धमकाया गया, मोदी सरकार जनता को इराकर-धमकाकर, सत्ता को खरीदकर, मित्र को सब बेचक मौज करने के फार्मूले पर चल रही है।

करारा जवाब देगी जनता

कांग्रेस ने अपनी पोस्ट में लिखा, इनकी नाकामी की बातें बहुत हैं। इतनी की कई किताबें लिख दी जाए लेकिन तब भी बहुत सी बातें छूट जाएंगी। अब जनता इनसे ऊब चुकी है, कर्नाटक का चुनाव इसका सबूत है, जहां जनता ने सीधे तौर पर वक्रूमोदी और उनकी भ्रष्ट सरकार को नकार दिया। ये असंतोष की लहर दक्षिण से चली है जो पूरे देश को खुद में समेट लेगी। जनता इंतजार में है और करारा जवाब देगी।

मल्लिकार्जुन खरगे को कोर्ट ने भेजा समन

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

संगरूर (पंजाब)। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पंजाब के संगरूर जिला कोर्ट के जज रमनदीप कौर ने शिकायतकर्ता हितेश भारद्वाज की शिकायत पर मल्लिकार्जुन खरगे को समन जारी किया है। कोर्ट ने 10 जुलाई 2023 को मल्लिकार्जुन खरगे को खुद अदालत में पेश होने के लिए ऑर्डर जारी किया है। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे अगर 10 जुलाई को न्यायालय में हाजिर नहीं होंगे, तो ऑर्डर में लिखा है कि उनकी गैरहाजिरी डालकर शिकायतकर्ता का पक्ष सुना जाएगा।

दरअसल बजरंग दल हिंद के राष्ट्रीय संस्थापक हितेश भारद्वाज की ओर से मल्लिकार्जुन खरगे पर 100 करोड़ रुपये की मानहानि का केस किया गया है। उन पर आरोप है कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के जारी किए गए मेनिफेस्टो में बजरंग दल की तुलना एंटी नेशनल यानि आतंकवादी संगठनों के साथ की गई है। साथ ही चुनाव जीतने पर बजरंग दल पर बैन लगाने की भी बात की गई है।कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि कांग्रेस पार्टी जाति या धर्म के आधार पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम मानते हैं कि कानून और संविधान पवित्र हैं और बजरंग दल, पीएफआई या जैसे व्यक्तियों और संगठनों द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, शत्रुता या घृणा को बढ़ावा देने वाले अन्य, चाहे बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समुदायों के बीच हों, कांग्रेस का घोषणापत्र, जिसे सर्व जनगंदा शांति थोटा (सभी समुदायों का शांतिपूर्ण उद्यान) कहा जाता है।

केंद्र सरकार ने भगवंत मान को दी 'जेड-प्लस' सुरक्षा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश और विदेश से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को खतरे की आशंका के मद्देनजर उन्हें जेड-प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी है। यहां आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 49 वर्षीय मान को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के वीआईपी सुरक्षा दस्ते द्वारा सुरक्षा मुहैया करायी जाएगी।

सूत्रों ने बताया कि मान को पूरे भारत में शीर्ष श्रेणी की जेड-प्लस सुरक्षा दी जाएगी और गृह मंत्रालय ने हाल में इसकी मंजूरी दी है. उन्होंने बताया कि सीआरपीएफ जल्द ही मान की सुरक्षा का जिम्मा संभालेगी और इसके लिए 55 सशस्त्र जवानों का दल भेजा गया है। सूत्रों ने बताया कि पंजाब पुलिस की सुरक्षा के अलावा दी गयी जेड-प्लस सुरक्षा मुख्यमंत्री के आवास और उनके परिवार के निकट सदस्यों को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सीमावर्ती राज्य में खालिस्तानी गतिविधियों को देखते हुए मुख्यमंत्री को खतरे की आशंका के आकलन के दौरान केंद्रीय एजेंसियों और सुरक्षा एजेंसियों ने मान को 'जेड-प्लस सुरक्षा देने की सिफारिश की।

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने लोस अध्यक्ष को लिखा पत्र, कहा-

प्रेस गैलरी से पत्रकारों का प्रतिबंध हटाया जाय

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने संसद परिसर के भीतर मीडिया कर्मियों के लिए कोविड-19 से पहले की तरह पूर्ण पहुंच बहाल करने की मांग की है। गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखे एक पत्र में, प्रेस क्लब के अध्यक्ष उमाकांत लखेरा और महासचिव विनय कुमार ने कहा कि 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा है, वे उनका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहेंगे। पिछले कई सत्रों में संसदीय कार्यवाही को कवर करने वाले पत्रकारों और रिपोर्टरों के प्रवेश पर लगातार प्रतिबंध लगाया गया है।

उन्होंने मांग की कि निष्क्रिय लोकसभा प्रेस सलाहकार समिति का तुरंत पुनर्गठन किया जाए। दोनों ने कहा कि मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्तरां, स्कूल और सार्वजनिक स्थानों जैसे विभिन्न क्षेत्रों ने पूर्व-महामारी स्तरों पर अपने संचालन को फिर से शुरू कर दिया था, यह ध्यान देना निराशाजनक है कि पत्रकारों को अभी भी संसद में उनकी सही पहुंच से वंचित किया जा रहा है। प्रेस गैलरी। उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों से संसद की कार्यवाही को कवर करने वाले बड़ी संख्या में पत्रकारों को स्थायी प्रेस गैलरी पास होने के बावजूद संसद की कार्यवाही को कवर करने के अवसर से वंचित किया जा रहा है।

प्रेस क्लब के नेताओं ने स्वीकार किया कि मीडियाकर्मियों पर ये प्रतिबंध 2020 के बजट सत्र के दौरान,कोविड-19 महामारी और समवर्ती सरकारी प्रतिबंधों के मद्देनजर लागू किए गए थे। उन्होंने विभिन्न अवसरों पर अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित करने के अपने बार-बार के प्रयासों का उल्लेख किया, जिसे उन्होंने बिना किसी तार्किक आधार या तर्क के अनावश्यक प्रतिबंध कहा, क्योंकि स्थिति धीरे-धीरे कम हो गई थी। पदाधिकारियों ने कहा कि संसद में पत्रकारों के प्रवेश पर प्रतिबंध का समर्थन किसी ठोस कारण या तर्क से नहीं किया गया, उन्होंने अपनी मजबूत भावना व्यक्त की कि ये प्रतिबंध मीडिया को नियंत्रित करने और प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से एक व्यापक एजेंडा का हिस्सा थे।

पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्रतिबंध दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोगों के लिए स्वतंत्र समाचारों और सूचनाओं के मुक्त प्रवाह को बाधित करने के लिए थे।

पत्र ने सुझाव दिया कि मीडिया को लगातार कोविड-19 दिशानिर्देशों की आड़ में बहाना बनाया जा रहा था, भले ही देश के बाकी हिस्सों में या दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर या सामुदायिक समारोहों आदि में इस तरह का कोई प्रतिबंध मौजूद नहीं है। दोनों पदाधिकारियों ने 5 मई 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की घोषणा की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया कि कोविड-19 अब वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है। उन्होंने चल रहे प्रतिबंधों पर गहरी चिंता दिखाई क्योंकि वे जनता के लिए महत्वपूर्ण सूचनाओं के प्रसार को गंभीर रूप से बाधित करते थे।

बारिश से गिरा तापमान, मौसम हुआ सुहाना

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। प्रदेश के कानपुर, लखनऊ सहित कई शहरों में सुबह से हो रही बारिश ने मौसम गुलजार कर दियाहै। इसकी वजह से लोगों को चिलचिलाती गर्मी में लोगों को राहत मिली है। बारिश और तेज हवाएं चलने से तापमान में करीब पांच से छह डिग्री की गिरावट भी दर्ज की गई है। आने वाले दो से तीन दिनों तक पूरे प्रदेश में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का अलर्ट जारी है। लखनऊ में गुरुवार सुबह-सुबह हुई झमाझम बारिश शुक्रवार सुबह भी जारी रही है।

बारिश की बूंदों ने जहां आम आदमी को गर्मी से राहत पहुंचाई तो वहीं दिनभर चली हवाओं ने राजधानी के अधिकतम तापमान में भी 6.8 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की।

पूरे यूपी में जारी किया तेज पानी का अलर्ट

गुरुवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 33.4 और न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश भर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं गरज और चमक के साथ मूसलधार के आसार जताए। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक दानिश ने बताया कि गुरुवार को सुल्तानपुर में 17 मिमी, चुर्क में 5.2 मिमी समेत प्रदेश भर में तेज हवाओं के साथ कुछ जिलों में छिटपुट बारिश दर्ज की गई है। शुक्रवार को प्रदेश भर में बारिश के आसार है। हवा के चलते अधिकतम तापमान में गिरावट रहेगी। अधिकतर जिलों में तापमान 40 डिग्री से कम ही रहेगा। शनिवार से बारिश में कमी आएगी। पश्चिमी यूपी में तेज बारिश के आसार हैं। अन्य जिलों में छिटपुट बारिश होगी।

रफ्तार से धूल भरी आंधी के आसार

प्रदेश भर में तेज हवाओं और झटपट बरसात से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सर्वाधिक तापमान बांदा में 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अन्य जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही रहा। हालांकि न्यूनतम तापमान में अधिक बदलाव दर्ज नहीं हुआ। सबसे कम तापमान मेरठ और नजीबाबाद में 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार को प्रदेशभर में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी भी आ सकती है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो सकता है।

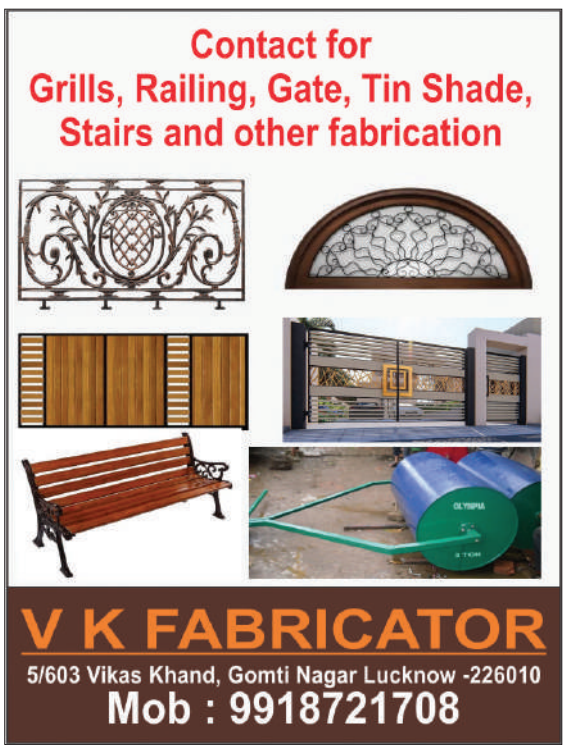

सुषमा ने संभाली लखनऊ के महापौर की कुर्सी

फोटो: सुमित कुमार

» नवनिर्वाचित पार्षदों के साथ हुआ शपथ ग्रहण

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। लखनऊ की नवनिर्वाचित मेयर सुषमा खड़कवाल ने नगर के पहले नागरिक के रुप में शपथ ले लिया। उनके साथ अन्य विजयी पार्षदों ने भी शपथ ग्रहण किया। समारोह गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ। इस अवसर पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक व संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद रहे। पूर्व मेयर संयुक्ता भाटिया और लखनऊ विकास प्राधिकरण की कमिश्नर रोशन जेकब भी नयी मेयर का साथ देने के लिए मौजूद रही।

समारोह में 3,000 से अधिक लोग शामिल हुए। लखनऊ नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक, कार्यक्रम में 1500 मेहमानों को निमंत्रण भेजा गया है। लखनऊ नगर निगम मेयर चुनाव में बीजेपी ने पिछले तीन दशक का रिकॉर्ड कायम रखा है। बीजेपी प्रत्याशी सुषमा खर्कवाल मेयर पद का चुनाव जीत चुकी हैं। उन्होंने रिकॉर्ड मार्जिन से सपा प्रत्याशी को शिकस्त दी। नगर निगम के इतिहास में यह दूसरी बार हुआ है जब किसी महिला मेयर को नगर निगम की कमान मिलेगी। शपथ लेते ही मेयर एलएमसी की प्रभारी का पद संभालेगी। नवनिर्वाचित महापौर सुषमा खरखवाल के बाद लखनऊ के सभी इलाको के नवनिर्वाचित पार्षद गणों ने एक के बाद एक शापत ग्रहण करी। सभी ने अपने इलाक़ों की पूरी तरह देख रेख की जिम्मेदारी लेने का फ़ैसला लिया।

नवनिर्वाचित महापौर ने थामी गदा

नवनिर्वाचित महापौर ने 107 साल पुरानी एक परंपरा को आगे बढ़ाया जिसकी जड़ें ब्रिटिश शाही दरबार में थीं - एक औपचारिक गदा, जिसे रॉयल गार्ड के रूप में भी जाना जाता है, जो सम्मान, शक्ति और शासन का प्रतीक है। महापौर के हाथ में गदा लिए बिना एलएमसी आवास आगे नहीं बढ़ सकता है। यह गदा एलएमसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बार शपथ ग्रहण समारोह में वीर नारियों एयर पूर्व सैनिकों के लिए सीट आरक्षित की गई हैं क्यूँकि महापौर शुष्मा खरखवाल के पति पूर्व सैनिक हैं। इस कारण रिटायर्ड सैनिकों की बड़ी संख्या शामिल कार्यक्रम में शामिल होगी। 2017 में बीजेपी प्रत्याशी संयुक्ता भाटिया लखनऊ की मेयर बनीं थी। उन्हें लखनऊ की पहली मेयर बनने की उपलब्धि हासिल हुई थी। समाजवादी पार्टी की मीरा वर्धन दूसरे नंबर पर थीं। लखनऊ नगर निगम 110 वार्डों में बंटा है। इनमें से 37 वार्ड महिलाओं के लिए रिजर्व हैं।

अभिषेक बनर्जी की जांच जारी रहेगी, सीबीआई-ईडी पर स्टे नहीं

» सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा

» जुर्माने पर लगाई रोक

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसियों को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने की अनुमति देने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। मामला पश्चिम बंगाल के स्कूलों में भर्ती अनियमितताओं से जुड़े करोड़ों रुपये के कथित घोटाले की जांच से जुड़ा हुआ है।

हालांकि, शीर्ष अदालत ने उनके खिलाफ 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अवकाश पीठ ने कहा कि वह अवकाश के बाद इस मामले की सुनवाई करेगी और मामले को 10 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। कोर्ट ने कहा किभर्ती घोटाले से जुड़े मामलों में अभिषेक से पूछताछ करने की जांच एजेंसियों को अनुमति देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

उमेश पाल हत्याकांड: दाखिल हुई चार्जशीट

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

प्रयागराज। उमेश पाल हत्याकांड में शुक्रवार को चार्जशीट दाखिल हुई। ज्ञात हो इसमें नौ आरोपियों का नाम हो सकता है। इनमें साजिशकर्ता सदाकत समेत वे शामिल हैं, जिन्हें उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी बनाया गया है और जो जेल में हैं। चार्जशीट दाखिल करने की 90 दिन की समयावधि में तीन दिन शेष हैं।

24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद से अब तक इस हत्या मामले में आठ आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा उम्रकैद की सजा काट रहे अतीक के वकील खान सौलत हनीफ को भी पुलिस आरोपी बना चुकी है। इस तरह से मौजूदा समय में इस मामले में कुल नौ लोग नैनी जेल में निरुद्ध हैं। प्रकरण में पहली गिरफ्तारी 27 फरवरी को हुई थी। पुलिस ने मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल से सदाकत खान को अवैध असलहा के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद 21 मार्च को अतीक अहमद के नौकर राकेश उर्फ लाला, ड्राइवर कैश अलावा हत्याकांड में रेकी करने वाले अख्तर कटरा, मो. सजद व नियाज अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी एक अप्रैल को हुई जब एसटीएफ ने अतीक के नौकर शारुप उर्फ शाहरुख को गिरफ्तार किया। चार अप्रैल को अतीक के बहनोई डॉ. अखलाक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। 27 अप्रैल को उमेश पाल हत्याकांड में खान सौलत हनीफ की रिमांड बनवाई गई। सूत्रों का कहना है कि इस मामले में जेल में निरुद्ध सभी नौ आरोपियों की हत्याकांड में संलिप्तता के पर्याप्त सबूत पुलिस जुटा चुकी है।

नौ आरोपियों के हो सकते हैं नाम

भाजपा नेता ने लिफ्ट देकर किया बलात्कार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई

आगरा। योगी जी के आदेश को उनकी पुलिस ही नकार रही है। एक पीड़िता अपने साथ हुए दुष्कर्म की शिकायत पुलिस को दे चुकी है पर यूपी पुलिस कोई कार्रवाई नही कर रही है। अब पीड़िता ने सीएम से मदद की गुहार लगाई है। मामला आगरा के थाना शमशाबाद क्षेत्र के एक गांव का है। सफेदपोश नेता और उसके साथियों पर महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है।

पीड़िता ने बताया कि कार में लिफ्ट देने के बहाने बैठाकर उसे सूनसान जगह ले जाकर दुष्कर्म किया गया। मामले में पुलिस पर सुनवाई नहीं करने का आरोप लगा। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर सफेदपोश नेता हरेंद्र सिंह व दो अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

मुख्यमंत्री से मिली पीड़िता

पीड़ित महिला के मुताबिक वह लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली। सीएम ने उसे आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। साथ ही पीड़ित महिला का कहना है कि आरोपी नेता उस पर रिश्तेदारों द्वारा सुलह करने का दबाव बना रहा है। साथ ही जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित महिला ने आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है।

ये हुई थी घटना

पीड़िता ने बताया कि विगत 12 फरवरी का यह घटनाक्र म है। नेता ने लिफ्ट देने के बहाने महिला को कार में बैठाकर दुष्कर्म किया था। मामले में तीन माह बाद कोर्ट के आदेश पर महिला की तहरीर पर थाना शमशाबाद में भाजपा से जुड़े नेता हरेंद्र सिंह और दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल भी कराया है और मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी हो चुके हैं। बावजूद इसके अभी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक **बबिता चतुर्वेदी** के लिए **4पीएम** आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (यूपी) से मुद्रित एवं प्रकाशित। **प्रधान संपादक**- अर्चना दयाल, **संपादक** - संजय शर्मा, **विधि सलाहकार**: सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, मोहम्मद हैदर, **वित्तीय सलाहकार**: संदीप बंसल, **कार्टूनिस्ट**: हसन जैदी, **दूरभाष**: 0522- 4078371 | **Email**: daily4pm@gmail.com | **website**: www.4pm.co.in | **RNI-UPHIN/2015/62233** डाक पंजी. सं- SSP/LW/NP-495/2018-2020
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।